RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

# नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 333
दि. 06.04.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा


# इतिहास, विरासत और राजनीति के संगम पर योगी का बड़ा बयान

उत्तर प्रदेश की राजधानी Lucknow में आयोजित भारतेंदु नाट्य अकादमी के स्वर्ण जयंती समारोह ने केवल एक सांस्कृतिक आयोजन का रूप नहीं लिया, बल्कि यह मंच इतिहास, विरासत और समकालीन राजनीति के विमर्श का केंद्र बन गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने अपने संबोधन में ऐतिहासिक व्यक्तित्वों, सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय चेतना को लेकर कई महत्वपूर्ण और चर्चित बयान दिए, जिनकी गूंज राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में सुनाई देने लगी है।

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे वीर नायक रहे हैं, जिन्हें समय के साथ भुला दिया गया या जिनकी भूमिका को पर्याप्त महत्व नहीं मिला। उन्होंने इस संदर्भ में विशेष रूप से Maharaja Suheldev का उल्लेख किया और कहा कि करीब एक हजार वर्षों के बाद उन्हें उचित सम्मान मिलना शुरू हुआ है। उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर सुहेलदेव ने आक्रमणकारी Salar Masud को पराजित किया था, वहां अब उनके नाम पर स्मारक और आयोजन हो रहे हैं। पहले उसी स्थान पर सालार मसूद के नाम से मेला आयोजित होता था, लेकिन अब लोगों की आस्था और ध्यान सुहेलदेव की ओर बढ़ रहा है।

अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने सालार मसूद को लेकर तीखे शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि वह एक आक्रमणकारी था, जो भारत को लूटने आया था और उसका चरित्र किसी माफिया से कम नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास में ऐसे तत्वों को महिमामंडित करने के बजाय उन वीरों को सम्मान दिया जाना चाहिए, जिन्होंने देश और समाज की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस बयान ने ऐतिहासिक विमर्श को एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक शिक्षा और रंगमंच की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि इतिहास को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उसे जीवंत रूप में नई पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूलों और कॉलेजों में नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से ऐतिहासिक गाथाओं को शामिल किया जाए। इस क्रम में उन्होंने Rani Lakshmibai और महाराजा सुहेलदेव जैसे वीरों की कहानियों को युवाओं तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। उनका मानना है कि रंगमंच और सिनेमा समाज को दिशा देने के प्रभावी माध्यम हैं और इनके जरिए सांस्कृतिक चेतना को मजबूत किया जा सकता है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौर को भी याद किया और कहा कि उस कठिन समय में सरकार ने संवेदनशीलता के साथ कार्य किया। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने और मुफ्त राशन उपलब्ध कराने जैसे कदम उठाए गए, जो सरकार की जनकल्याणकारी सोच को दर्शाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब शासन संवेदनशील नहीं होता, तब समाज को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

भारतेंदु नाट्य अकादमी के 50 वर्ष पूरे होने के इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने Bharatendu Harishchandra के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनकी रचनाएं आज भी समाज को जागरूक करने का कार्य कर रही हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सांस्कृतिक संस्थानों को शिक्षा के साथ जोड़ना समय की आवश्यकता है, ताकि युवा पीढ़ी अपनी जड़ों और परंपराओं को बेहतर तरीके से समझ सके।

स्वर्ण जयंती समारोह के पहले दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नाट्य प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया, जिसमें देशभर से आए कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान 'आनंद मठ' जैसे ऐतिहासिक नाटकों का मंचन भी किया गया, जिसे मुख्यमंत्री ने सराहा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन न केवल कला को बढ़ावा देते हैं, बल्कि समाज में जागरूकता और राष्ट्रीय भावना को भी सशक्त करते हैं।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 15 पूर्व छात्रों और रंगकर्मियों को सम्मानित भी किया, जिन्होंने रंगमंच और सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का सम्मान करना समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि यही लोग हमारी परंपराओं और मूल्यों को जीवित रखते हैं।

यह आयोजन केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं, बल्कि एक व्यापक संदेश भी लेकर आया है कि इतिहास, संस्कृति और आधुनिक समाज के बीच संतुलन बनाना कितना आवश्यक है। मुख्यमंत्री के बयान जहां एक ओर ऐतिहासिक पुनर्मूल्यांकन की ओर संकेत करते हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी दर्शाते हैं कि सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर प्रयास करने होंगे। इस समारोह ने यह स्पष्ट कर दिया कि रंगमंच और इतिहास के माध्यम से समाज में नई चेतना जगाने की दिशा में अभी और भी व्यापक कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

## पश्चिमी विक्षोभ का असर, दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलेगा

देशभर में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है और इसका सीधा असर उत्तर भारत के बड़े हिस्से में देखने को मिलेगा। India Meteorological Department यानी भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी-तूफान का दौर शुरू हो सकता है। खासतौर पर Delhi NCR में रविवार रात से मौसम अचानक बदल सकता है, जिससे आम जनजीवन पर असर पड़ने की पूरी संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार राजधानी New Delhi और उसके आसपास के क्षेत्रों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, दक्षिण दिल्ली और नोएडा में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने की आशंका जताई गई है। हालांकि यह सिस्टम पूरी तरह से एकसमान नहीं होगा, बल्कि छिटपुट रूप में प्रभाव डालेगा। इसका मतलब यह है कि कुछ इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है, जबकि पास के इलाके पूरी तरह सूखे रह सकते हैं। अनुमान के मुताबिक एनसीआर के लगभग 50 से 60 प्रतिशत हिस्से पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी क्षेत्र अचानक बदलते मौसम का सामना कर सकते हैं।

इस पूरे बदलाव की मुख्य वजह पश्चिमी विक्षोभ को माना जा रहा है, जो भूमध्य सागर क्षेत्र से आने वाला एक नमी युक्त मौसमी तंत्र होता है। यह तंत्र जब उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय होता है, तो मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिलता है। हाल ही में 3 और 4 अप्रैल को सक्रिय रहे एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी तक बना हुआ है, जिसके कारण अप्रैल के महीने में भी अगस्त जैसी उमस और बादलों की स्थिति बन रही है। अब एक और नया और अधिक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ 7 से 9 अप्रैल के बीच सक्रिय होने जा रहा है, जो मौसम को और अधिक अस्थिर बना सकता है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस नए सिस्टम का प्रभाव केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के करीब 30 से 40 प्रतिशत हिस्से पर इसका असर देखने को मिलेगा। इसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के कई इलाके शामिल हैं। इन क्षेत्रों में कहीं तेज बारिश, कहीं ओलावृष्टि और कहीं तेज हवाओं के साथ तूफान की स्थिति बन सकती है।

इस बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से उन किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है, जिनकी गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार है। उन्हें 6 अप्रैल से पहले ही फसल काट लेने की सलाह दी गई है, ताकि संभावित ओलावृष्टि और बारिश से नुकसान को कम किया जा सके। हाल ही में कई राज्यों में गिरे बड़े-बड़े ओलों ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है और अब एक बार फिर ऐसी स्थिति बनने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि 7 से 10 अप्रैल के बीच यह मौसमीय गतिविधि अपने चरम पर रहेगी। इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां तेज हवाओं और बिजली गिरने का खतरा अधिक होता है। शहरों में रहने वाले लोगों को भी सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें।

हालांकि यह राहत की बात है कि यह सिस्टम ज्यादा लंबे समय तक सक्रिय नहीं रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 10 अप्रैल के बाद यह पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने लगेगा और इसके बाद मौसम धीरे-धीरे सामान्य होने लगेगा। लेकिन इसके साथ ही गर्मी एक बार फिर तेजी से वापसी करेगी और अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में तापमान में तेजी से वृद्धि देखी जा सकती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिन मौसम के लिहाज से काफी उतार-चढ़ाव भरे रहने वाले हैं। जहां एक ओर बारिश और ठंडी हवाएं अस्थायी राहत देंगी, वहीं दूसरी ओर ओलावृष्टि और तेज तूफान नुकसान का कारण भी बन सकते हैं।

## हाईकोर्ट में खुद उतरेंगे केजरीवाल, शराब नीति मामले में सुनवाई से पहले बढ़ा सियासी और कानूनी तापमान

देश की राजधानी New Delhi में कथित आबकारी नीति मामले ने एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। इस बहुचर्चित मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने एक असाधारण कदम उठाते हुए स्वयं दिल्ली हाईकोर्ट में पेश होकर अपनी दलील रखने का निर्णय लिया है। किसी शीर्ष स्तर के सक्रिय राजनेता द्वारा अदालत में व्यक्तिगत रूप से पैरवी करना भारतीय राजनीति और न्यायिक प्रक्रिया के संदर्भ में एक दुर्लभ घटना मानी जा रही है, जिससे इस मामले की गंभीरता और भी बढ़ गई है।

यह मामला उस समय और अधिक जटिल हो गया, जब निचली अदालत ने पहले केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के समन की अवहेलना के आरोप से बरी कर दिया था। इसके बाद Enforcement Directorate ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ईडी का कहना है कि समन की अवहेलना एक गंभीर मामला है और निचली अदालत का फैसला तथ्यों और कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इसी के साथ इस प्रकरण ने एक बार फिर से जांच एजेंसियों और राजनीतिक नेतृत्व के बीच टकराव की स्थिति को उजागर कर दिया है। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ तब आया, जब केजरीवाल और अन्य आरोपियों ने हाईकोर्ट में 'रिक्यूजल' यानी जज के खुद को सुनवाई से अलग करने की मांग रखी है। यह अर्जी Delhi High Court की न्यायाधीश जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष दाखिल की गई है। केजरीवाल पक्ष का तर्क है कि इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि इसे किसी अन्य पीठ को सौंपा जाए। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जस्टिस शर्मा के कुछ आदेशों को पहले उच्चतम न्यायालय द्वारा पलटा जा चुका है, जिससे उनके समक्ष निष्पक्षता को लेकर संदेह उत्पन्न होता है।

हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि 'रिक्यूजल' की मांग अपने आप में एक संवेदनशील और असाधारण प्रक्रिया होती है, जिसे अदालत बहुत सावधानी से परखती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होती है, इसलिए इस प्रकार की अर्जी पर निर्णय लेते समय अदालत सभी तथ्यों, तर्कों और परिस्थितियों का गहन विश्लेषण करती है। ऐसे मामलों में यह भी देखा जाता है कि क्या वास्तव में कोई ठोस आधार है, जिससे यह लगे कि सुनवाई प्रभावित हो सकती है, या फिर यह केवल रणनीतिक कदम है।

इस मामले की सुनवाई सोमवार को प्रस्तावित है, जिसमें यह तय होना है कि अदालत रिक्यूजल अर्जी को स्वीकार करती है या उसे खारिज कर देती है। यदि अदालत इस अर्जी को स्वीकार करती है, तो मामला किसी अन्य पीठ के पास स्थानांतरित हो जाएगा, जिससे सुनवाई की दिशा और गति दोनों प्रभावित हो सकती हैं। वहीं, यदि अर्जी खारिज होती है, तो मौजूदा पीठ ही आगे की सुनवाई जारी रखेगी, जो केजरीवाल और अन्य आरोपियों के लिए एक नई कानूनी चुनौती खड़ी कर सकती है। केजरीवाल का खुद अदालत में पेश होकर अपनी बात रखना इस मामले को और अधिक राजनीतिक रंग दे रहा है। आम तौर पर इस स्तर के नेता अपने वकीलों के माध्यम से ही अदालत में पक्ष रखते हैं, लेकिन इस बार उनका स्वयं सामने आना यह दर्शाता है कि वह इस मुद्दे को केवल कानूनी ही नहीं, बल्कि जन-धारणा के स्तर पर भी महत्वपूर्ण मानते हैं। यह कदम उनके समर्थकों के बीच एक मजबूत संदेश देने का प्रयास भी हो सकता है कि वह अपने खिलाफ लगे आरोपों का सीधे सामना करने के लिए तैयार हैं।

## कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट कांड में नया खुलासा फरार डॉक्टर के वायरल वीडियो से जांच में तेजी

उत्तर प्रदेश के Kanpur में सामने आए चर्चित किडनी ट्रांसप्लांट कांड ने अब एक और सनसनीखेज मोड़ ले लिया है। इस मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल फरार डॉक्टर अफजाल का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद जांच एजेंसियों की सक्रियता और बढ़ गई है। वीडियो में आरोपी डॉक्टर को भारी मात्रा में नकदी के साथ देखा जा रहा है, जिससे इस पूरे मामले की गंभीरता और गहराती नजर आ रही है।

यह मामला तब उजागर हुआ था जब 31 मार्च को शहर के Ahuja Hospital में संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर छापेमारी की गई। शुरुआती जांच में ही यह स्पष्ट हो गया था कि यहां किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर एक संगठित फर्जीवाड़ा चल रहा था, जिसमें डोनर और रिसीवर के बीच अवैध तरीके से प्रत्यारोपण कराया जा रहा था। इसके बदले बड़ी रकम का लेन-देन किया जाता था, जो पूरे नेटवर्क के सक्रिय होने का संकेत देता है।

मामले में अब तक कई डॉक्टरों और सहयोगियों समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मुख्य आरोपी डॉक्टर अफजाल अब भी फरार है। इसी बीच सामने आए वीडियो ने पुलिस की जांच को एक नई दिशा दे दी है। वायरल वीडियो में डॉक्टर अफजाल एक बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके आसपास 500-500 रुपये के नोटों की गड्डियां रखी हुई हैं। वीडियो में एक अन्य व्यक्ति भी नजर आ रहा है, जिसे उसका ड्राइवर बताया जा रहा है।

इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस अब कई अहम सवालों के जवाब तलाशने में जुट गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वीडियो कब का है और इसमें दिख रही नकदी का स्रोत क्या है। क्या यह रकम अवैध ट्रांसप्लांट से जुड़ी है या किसी अन्य गतिविधि से संबंधित है, इसकी गहन जांच की जा रही है। इसके साथ ही यह भी जांच का विषय है कि यह वीडियो किसने रिकॉर्ड किया और इसे सोशल मीडिया पर किस उद्देश्य से वायरल किया गया।

जांच एजेंसियां अब इस मामले को केवल एक अस्पताल या कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं मान रही हैं, बल्कि इसे एक बड़े संगठित गिरोह के रूप में देख रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि यह नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हो सकता है और इसमें दलालों, मेडिकल स्टाफ और अन्य सहयोगियों की भी भूमिका हो सकती है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या अन्य अस्पतालों में भी इसी तरह की गतिविधियां संचालित हो रही थीं।

फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। उसके मोबाइल फोन की लोकेशन, कॉल डिटेल्स और आर्थिक लेन-देन की भी जांच की जा रही है, ताकि उसके नेटवर्क और छिपने के स्थानों का पता लगाया जा सके। पुलिस सूत्रों के अनुसार, जल्द ही इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस पूरे प्रकरण ने स्वास्थ्य व्यवस्था और चिकित्सा नैतिकता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। किडनी ट्रांसप्लांट जैसे संवेदनशील और जीवनरक्षक चिकित्सा प्रक्रिया का इस तरह दुरुपयोग न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह मानवता के खिलाफ भी अपराध है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों पर सख्त कार्रवाई और निगरानी तंत्र को मजबूत करना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

प्रशासन के लिए यह मामला एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है, जहां उसे न केवल आरोपियों को पकड़ना है, बल्कि इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करना भी जरूरी है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि चिकित्सा संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। फिलहाल पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है और पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कर रही है। वायरल वीडियो ने जहां एक ओर जांच को गति दी है, वहीं दूसरी ओर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस कांड की परतें अभी पूरी तरह खुलनी बाकी हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं, जिनसे यह तय होगा कि इस अवैध कारोबार की जड़ें कितनी गहरी हैं।


नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

# हिमाचल निकाय चुनावों में आरक्षण का समीकरण महिलाओं को बढ़ी भागीदारी से सियासत में हलचल

हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायत और शहरी निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी बीच सरकार द्वारा जारी आरक्षण रोस्टर ने स्थानीय सियासत को नया आयाम दे दिया है। राजधानी Shimla से जारी इस अधिसूचना के तहत राज्य के कुल 49 शहरी निकायों में आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें महिलाओं को 16 सीटें आरक्षित की गई हैं। यह फैसला न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे स्थानीय राजनीतिक समीकरणों में भी व्यापक बदलाव की संभावनाएं बन गई हैं।

शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए आरक्षण का निर्धारण विधिवत प्रक्रिया के तहत किया गया है। यह प्रक्रिया कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप पूरी की गई है, ताकि चुनावों में पारदर्शिता और सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। फिलहाल यह आरक्षण रोस्टर नगर परिषद और नगर पंचायत स्तर तक सीमित रखा गया है, जबकि राज्य के चार नगर निगमों के लिए अलग से आरक्षण सूची जारी की जाएगी, जिससे आने वाले दिनों में और राजनीतिक हलचल बढ़ने की संभावना है।

आरक्षण के इस नए ढांचे में महिलाओं की भागीदारी को विशेष प्राथमिकता दी गई है। कुल 49 निकायों में से 16 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होना यह दर्शाता है कि सरकार स्थानीय निकायों में महिला नेतृत्व को मजबूत करना चाहती है। यह कदम ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। इससे न केवल महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा, बल्कि नीति निर्माण में भी उनकी भूमिका अधिक प्रभावी हो सकेगी।

अगर आरक्षण के विस्तृत आंकड़ों पर नजर डालें तो अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए 10 निकाय आरक्षित किए गए हैं, जिनमें से 5 सीटें एससी महिला वर्ग के लिए निर्धारित हैं। इस श्रेणी में ऊना का दौलतपुर, चंबा नगर परिषद, कुल्लू का बंजार, बिलासपुर नगर परिषद और मंडी का सुंदरनगर प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा मेहतपुर बसदेहड़ा, नगरोटा बगवां, घुमारवीं, रोहडू और चिड़गांव को भी एससी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। इस प्रकार सामाजिक न्याय और समावेशिता को ध्यान में रखते हुए आरक्षण का संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

वहीं अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग को इस बार केवल एक नगर निकाय में प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिसके तहत कांगड़ा जिले का शाहपुर आरक्षित किया गया है। इसके अलावा सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 11 नगर निकाय सुरक्षित किए गए हैं, जिनमें निरमंड, अर्की, ज्वालामुखी, कंडाघाट, संतोषगढ़, अंब, गगरेट, कुल्लू, नूरपुर, ठियोग और टाहलीवाल शामिल हैं। यह वितरण यह दर्शाता है कि आरक्षण नीति को विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

इस पूरी प्रक्रिया में अदालत के निर्देशों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। प्रशासन के लिए यह प्राथमिकता रही है कि आरक्षण की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो, ताकि चुनाव कार्यक्रम में किसी प्रकार की बाधा न आए। जैसे ही चुनाव अधिसूचना जारी होगी, प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो जाएंगी।

दूसरी ओर, पंचायत चुनावों की तैयारियां भी समानांतर रूप से आगे बढ़ रही हैं। सूत्रों के अनुसार अप्रैल के तीसरे सप्ताह के अंत तक पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी की जा सकती है और चुनाव तीन चरणों में कराए जाने की संभावना है। राज्य सरकार को 7 अप्रैल तक पंचायत स्तर के आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप देना है, जिसके बाद चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा की जाएगी।

मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य भी तेजी से जारी है। एक अप्रैल तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए मतदाताओं को सूची में शामिल किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में लगभग 19 से 20 दिन का समय लगने का अनुमान है, जिससे चुनाव अधिसूचना की समय-सीमा पर थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि प्रशासन इस पूरी प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए प्रयासरत है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार के निकाय चुनावों में आरक्षण का यह नया समीकरण कई क्षेत्रों में सत्ता संतुलन को बदल सकता है। जिन सीटों पर आरक्षण बदला है, वहां पुराने दावेदारों को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी, जबकि नए उम्मीदवारों के लिए अवसर भी खुलेंगे। विशेष रूप से महिलाओं के लिए बढ़ी हुई सीटों की संख्या ने राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति में बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया है।

कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में निकाय चुनावों की तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच चुकी हैं और आरक्षण रोस्टर के जारी होते ही राजनीतिक माहौल पूरी तरह सक्रिय हो गया है। आने वाले दिनों में चुनाव अधिसूचना के साथ ही यह सरगर्मी और तेज होगी और प्रदेश की स्थानीय राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करेगी, जहां सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का नया संतुलन देखने को मिलेगा।

# सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम से बदली तस्वीर, 119 महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर, सुरक्षित परिवहन को मिली नई दिशा

Lucknow। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण को एक साथ मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार की 'सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम' योजना तेजी से प्रभाव दिखा रही है। इस पहल ने न केवल महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार का अवसर दिया है, बल्कि समाज में सुरक्षित और भरोसेमंद परिवहन व्यवस्था की नई मिसाल भी पेश की है। योजना के तहत अब तक 119 महिलाएं ई-रिक्शा संचालित कर अपने परिवार का सहारा बन चुकी हैं, जिससे उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता और आत्मविश्वास दोनों बढ़े हैं। यह कार्यक्रम खास तौर पर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। लंबे समय से परिवहन की असुरक्षा और सीमित संसाधनों के कारण छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में महिला चालकों द्वारा संचालित ई-रिक्शा सेवा एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरी है, जिसने सामाजिक सोच में भी सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है।

योजना के पहले चरण में Ayodhya, Gorakhpur, Varanasi, Kaushambi और Jhansi जिलों में इसकी शुरुआत की गई, जहां से उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। इन पांच जिलों में 119 महिलाओं को ई-रिक्शा उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जिससे वे न केवल आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। इसके साथ ही 629 महिलाओं को ई-रिक्शा संचालन और ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया गया है, जबकि 244 महिलाओं को वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, जो इस योजना के व्यवस्थित क्रियान्वयन को दर्शाता है।

राज्य सरकार इस पहल को और व्यापक बनाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। दूसरे चरण में Prayagraj, Mirzapur, Bhadohi, Sonbhadra, Deoria, Lakhimpur Kheri और Sitapur सहित कुल आठ जिलों में इस योजना को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार इस मॉडल को पूरे प्रदेश में विस्तार देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कार्यक्रम Uttar Pradesh State Rural Livelihood Mission के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, जिसमें तकनीकी सहयोग Development Alternatives द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इस साझेदारी ने योजना को तकनीकी और संचालनात्मक रूप से मजबूत आधार दिया है, जिससे इसके परिणाम और अधिक प्रभावी बन पाए हैं।

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका आर्थिक प्रभाव है। इससे जुड़ी महिलाओं की औसत वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक पहुंच गई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है, बल्कि उन्हें समाज में एक नई पहचान भी दिला रहा है। अब ये महिलाएं सिर्फ गृहिणी नहीं, बल्कि परिवार की कमाऊ सदस्य बनकर निर्णय लेने में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह पहल बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है। छात्राओं को स्कूल और कॉलेज आने-जाने में सुरक्षा का भरोसा मिला है, वहीं कामकाजी महिलाओं के लिए भी यह सेवा सुविधाजनक और सुरक्षित विकल्प बन चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां परिवहन के साधन सीमित होते हैं, वहां यह योजना एक बड़ी राहत लेकर आई है। साथ ही, इससे गांवों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं, जिससे पलायन की समस्या पर भी आंशिक नियंत्रण संभव हो सकता है।

राज्य सरकार का मानना है कि 'सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम' महिला सुरक्षा, सम्मानजनक परिवहन और स्वरोजगार—इन तीनों लक्ष्यों को एक साथ साधने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। आने वाले समय में इसे और अधिक जिलों तक विस्तारित करने की योजना है, ताकि प्रदेश के हर कोने में महिलाएं इस पहल का लाभ उठा सकें और सामाजिक-आर्थिक बदलाव की इस प्रक्रिया को और गति मिल सके। स्पष्ट है कि यह योजना केवल एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनती जा रही है, जहां महिलाएं अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर नई ऊंचाइयों को छू रही हैं और समाज को एक सकारात्मक दिशा दे रही हैं।

# विकास पर सियासी वार-पलटवार, बिहार की हालत को लेकर तेजस्वी का बड़ा हमला

राजधानी Patna में एक बार फिर विकास के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है और आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष Tejashwi Yadav ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया है कि बिहार पिछले दो दशकों में विकास के लगभग हर प्रमुख पैमाने पर देश के सबसे निचले पायदान पर बना हुआ है। उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीतिक फिजा में हलचल तेज हो गई है और सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई है।

तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए जारी अपने बयान में कहा कि पिछले करीब 21 वर्षों में राज्य में जो सरकारें रहीं, उनके कार्यकाल में बिहार साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, कृषि आय, निवेश, उपभोग और बिजली खपत जैसे बुनियादी संकेतकों पर लगातार पिछड़ता गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के बड़े दावों के बावजूद जमीनी स्तर पर स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं दिखता और कई क्षेत्रों में ठहराव की स्थिति बनी हुई है।

नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि जहां विकास के सकारात्मक संकेतकों में बिहार पीछे है, वहीं नकारात्मक पहलुओं में स्थिति चिंताजनक है। उनके अनुसार अपराध, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे मामलों में राज्य शीर्ष राज्यों में गिना जाता है। उन्होंने इसे सरकार की नीतिगत विफलता करार देते हुए कहा कि अगर योजनाएं सही तरीके से लागू होतीं, तो बिहार की तस्वीर कुछ और होती।

शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी तेजस्वी यादव ने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य में स्कूलों में ड्रॉपआउट दर काफी अधिक है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं हो पाई है। इसके साथ ही पुपिल-टीचर अनुपात में असंतुलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही। यह स्थिति भविष्य की पीढ़ी के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है।

स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा और दावा किया कि सरकारी अस्पतालों में करीब 58 प्रतिशत डॉक्टरों के पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी के कारण आम लोगों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या और अधिक गंभीर है, जहां बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं।

तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि वह चुनावी वादों और घोषणाओं के जरिए असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री Nitish Kumar और उपमुख्यमंत्रियों को सार्वजनिक बहस की चुनौती देते हुए कहा कि वे विकास के आंकड़ों पर खुलकर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार अपने दावों को लेकर आश्वस्त है, तो उसे इस तरह की बहस से पीछे नहीं हटना चाहिए।

तेजस्वी यादव के इन आरोपों को Indian National Congress का भी समर्थन मिला है। पार्टी के प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि राज्य में करीब 20 वर्षों से राजग की सरकार है और केंद्र में भी पिछले 12 वर्षों से वही गठबंधन सत्ता में है, इसके बावजूद बिहार अपेक्षित विकास नहीं कर सका। उन्होंने इसे नीतिगत विफलता बताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार अपने कामकाज का स्पष्ट हिसाब दे। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में विकास के मुद्दे को फिर से केंद्र में ला दिया है। जहां एक ओर विपक्ष सरकार की उपलब्धियों पर सवाल उठा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष अपने कामकाज का बचाव करने में जुटा है। आने वाले समय में यह मुद्दा और अधिक तूल पकड़ सकता है, खासकर चुनावी माहौल के करीब आते ही। विशेषज्ञों का मानना है that विकास जैसे मुद्दे पर होने वाली यह बहस लोकतंत्र के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे सरकारों की जवाबदेही तय होती है और जनता को सही जानकारी मिलती है। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि इस तरह की बहस आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित हो, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

# गैस एजेंसी में बड़ा घोटाला उजागर, 1295 सिलेंडरों की हेराफेरी पर कड़ी कार्रवाई

Amethi जिले में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन द्वारा की गई सख्त छापेमारी में कुल 1295 सिलेंडरों की अनियमितता उजागर हुई है, जिसके बाद गैस एजेंसी संचालक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई तेज कर दी गई है। यह मामला न केवल सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि आम उपभोक्ताओं के अधिकारों के साथ गंभीर खिलवाड़ की ओर भी इशारा करता है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सप्लाई विभाग की टीम ने दुर्गापुर रोड स्थित केवलापुर गांव में संचालित प्रकाश गैस एजेंसी के गोदाम पर अचानक छापा मारा। यह कार्रवाई 'संपूर्ण समाधान दिवस' के दौरान प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई थी, जिसमें एजेंसी द्वारा सिलेंडरों की कालाबाजारी और रिकॉर्ड में हेराफेरी की आशंका जताई गई थी। जब टीम ने गोदाम में उपलब्ध सिलेंडरों का भौतिक सत्यापन किया, तो विभागीय रिकॉर्ड से बड़ा अंतर सामने आया, जिसने पूरे मामले को गंभीर बना दिया।

जांच के दौरान सबसे बड़ी गड़बड़ी 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडरों में पाई गई। यहां 556 भरे हुए सिलेंडर रिकॉर्ड में तो दर्ज थे, लेकिन मौके पर मौजूद नहीं मिले। इसके विपरीत, 432 खाली सिलेंडर अतिरिक्त पाए गए, जिनका कोई स्पष्ट हिसाब नहीं था। इसके अलावा 17 डिफेक्टिव सिलेंडर भी गायब पाए गए, जो सुरक्षा मानकों के लिहाज से बेहद चिंताजनक है।

इसी तरह 10 किलोग्राम के कंपोजिट सिलेंडरों में भी अनियमितता उजागर हुई, जहां 9 भरे सिलेंडर कम और 10 खाली सिलेंडर अधिक पाए गए। व्यावसायिक उपयोग वाले 19 किलोग्राम के सिलेंडरों में 30 भरे सिलेंडर गायब थे, जबकि 212 खाली सिलेंडरों का कोई रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं था। 5 किलोग्राम श्रेणी के सिलेंडरों में भी 29 भरे सिलेंडर पूरी तरह से नदारद मिले। इन सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल 1295 सिलेंडरों की हेराफेरी की पुष्टि हुई है, जो इस घोटाले के बड़े पैमाने को दर्शाता है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी संजय चौहान की अनुमति से एजेंसी संचालक मनदीप सिंह के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 तथा पेट्रोलियम गैस आदेश, 2000 के उल्लंघन में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से गोदाम में मौजूद सभी सिलेंडरों को बारहमासी स्थित राजाराम गैस एजेंसी में स्थानांतरित कर दिया है, ताकि उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आए।

जांच टीम में शामिल पूर्ति निरीक्षक अरुण कुमार पांडेय ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से शिकायत के आधार पर की गई थी और जांच के दौरान सामने आए तथ्य बेहद गंभीर हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की विस्तृत रिपोर्ट Indian Oil Corporation को भेज दी गई है, जहां से विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इस पूरे घटनाक्रम ने गैस वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की अनियमितताएं न केवल उपभोक्ताओं के हितों को प्रभावित करती हैं, बल्कि सरकारी सब्सिडी व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाती हैं। यदि समय रहते इस पर कठोर नियंत्रण नहीं किया गया, तो यह समस्या और व्यापक रूप ले सकती है।

फिलहाल प्रशासन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इस तरह के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर अन्य एजेंसियों की भी जांच की जाएगी, ताकि पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सके।

# काशी में परंपरा और तकनीक का संगम, 'विक्रमादित्य वैदिक घड़ी' बनी आकर्षण का केंद्र

Varanasi। धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की नगरी काशी एक बार फिर अपनी प्राचीन विरासत और आधुनिक तकनीक के अनूठे समन्वय को लेकर चर्चा में है। विश्व प्रसिद्ध Shri Kashi Vishwanath Temple परिसर में स्थापित 'विक्रमादित्य वैदिक घड़ी' ने न केवल श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, बल्कि भारतीय कालगणना की समृद्ध परंपरा को भी जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav द्वारा बाबा विश्वनाथ को समर्पित यह भेंट अब काशी की पहचान का एक नया अध्याय बनती जा रही है।

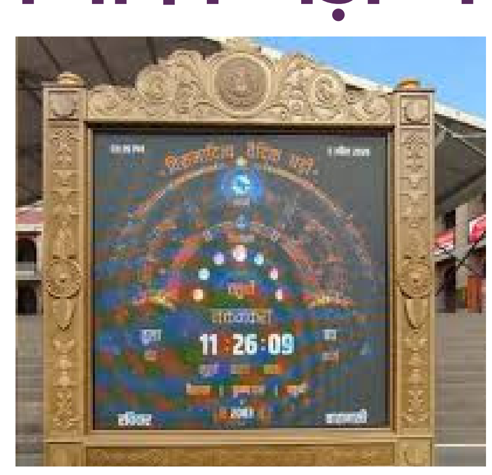


काशी, जिसे सनातन परंपराओं की जीवित नगरी कहा जाता है, हमेशा से ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का केंद्र रही है। यहां हर परंपरा के पीछे एक गहरी वैज्ञानिक और दार्शनिक सोच छिपी होती है। ऐसे में 'विक्रमादित्य वैदिक घड़ी' की स्थापना केवल एक औपचारिक पहल नहीं, बल्कि उस प्राचीन ज्ञान को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, जिसे समय के साथ धीरे-धीरे भुला दिया गया था। यह घड़ी भारतीय समय-गणना की उस प्रणाली को दर्शाती है, जिसमें केवल घंटे और मिनट ही नहीं, बल्कि तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार जैसे सूक्ष्म पहलुओं को भी शामिल किया जाता है।

मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा के अनुसार, इस घड़ी का उद्देश्य केवल समय बताना नहीं है, बल्कि लोगों को भारतीय कालगणना के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पक्ष से परिचित कराना भी है। भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान में समय की गणना अत्यंत सूक्ष्म और सटीक मानी जाती रही है। प्राचीन काल में ऋषि-मुनियों ने सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति के आधार पर जो समय-निर्धारण प्रणाली विकसित की थी, वही आज इस वैदिक घड़ी के माध्यम से आधुनिक तकनीक के साथ प्रस्तुत की गई है।

घड़ी की स्थापना के बाद से ही मंदिर परिसर में इसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देश-विदेश से आने वाले पर्यटक, शोधार्थी और आम श्रद्धालु इस अनोखी घड़ी को देखने और समझने के लिए विशेष रुचि दिखा रहे हैं। कई लोग इसे केवल एक धार्मिक वस्तु नहीं, बल्कि भारतीय वैज्ञानिक विरासत का प्रतीक मान रहे हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार, शुरुआती दिनों में ही हजारों लोगों ने इस घड़ी को देखा और इसके बारे में जानकारी प्राप्त की, जिससे इसकी बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

काशी में इस तरह की पहल का एक सामाजिक और शैक्षणिक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर श्रद्धालु इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर युवा पीढ़ी इसे भारतीय विज्ञान और ज्योतिष के अध्ययन के रूप में भी समझने लगी है। यह घड़ी लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिक समय-गणना प्रणाली के पहले भी भारत में कितनी विकसित और सटीक पद्धतियां मौजूद थीं। विशेषज्ञों का मानना है कि 'विक्रमादित्य वैदिक घड़ी' भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल न केवल सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का भी काम करती है। काशी जैसे शहर में, जहां हर गली और हर घाट में इतिहास और अध्यात्म की गूंज सुनाई देती है, वहां इस तरह की तकनीकी पहल एक नई ऊर्जा और पहचान प्रदान करती है।

इसके साथ ही यह घड़ी पर्यटन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। काशी आने वाले विदेशी पर्यटक, जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को समझने के लिए उत्सुक रहते हैं, उनके लिए यह एक अनूठा अनुभव बन सकता है। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत की प्राचीन वैज्ञानिक उपलब्धियों को वैश्विक स्तर पर पहचान भी मिलेगी।

इस पहल के पीछे एक बड़ा संदेश भी छिपा है—कि आधुनिकता की दौड़ में अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए। 'विक्रमादित्य वैदिक घड़ी' यह दर्शाती है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक एक साथ मिलकर कैसे समाज को नई दिशा दे सकते हैं। यह केवल एक घड़ी नहीं, बल्कि समय के उस दर्शन का प्रतीक है, जो भारतीय संस्कृति की आत्मा में बसता है। कुल मिलाकर, काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थापित यह वैदिक घड़ी आस्था, विज्ञान और संस्कृति का ऐसा संगम बनकर उभरी है, जो न केवल वर्तमान पीढ़ी को आकर्षित कर रही है, बल्कि भविष्य के लिए भी एक प्रेरणास्रोत बनती जा रही है। आने वाले समय में यह पहल अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है, जहां परंपरा और तकनीक का ऐसा ही संतुलित मेल देखने को मिले।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com* navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

# 300 फीट गहरी खाई में गिरी ट्रैवलर, कुल्लू हादसे में चार की मौत, 19 घायल

Kullu/Shimla। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में शनिवार देर रात हुआ एक भीषण सड़क हादसा चार परिवारों के लिए जिंदगी भर का दुख छोड़ गया, जबकि उन्नीस अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बंजार उपमंडल के घियागी क्षेत्र में जलोड़ी दर्रा से लौट रही एक टेंपो ट्रैवलर अचानक अनियंत्रित होकर लगभग तीन सौ फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के समय वाहन में कुल तेईस लोग सवार थे, जिनमें दो छोटे मासूम बच्चे भी शामिल थे। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और पहाड़ों की खामोशी दर्दनाक कराहों में बदल गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रैवलर जलोड़ी दर्रा से वापस लौट रही थी। जैसे ही वाहन घियागी के पास एक तीखे और खतरनाक मोड़ पर पहुंचा, चालक संतुलन खो बैठा। बताया जा रहा है कि वाहन की गति अधिक थी और मोड़ काफी संकरा था, जिसके कारण चालक वाहन को संभाल नहीं सका और देखते ही देखते ट्रैवलर सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

दुर्घटना देर रात होने के कारण राहत एवं बचाव कार्य में शुरुआत में भारी दिक्कतें आईं। अंधेरा, दुर्गम पहाड़ी रास्ते और गहरी खाई ने स्थिति को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। सबसे पहले आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने बिना किसी संसाधन के ही साहस दिखाते हुए खाई में उतरकर घायलों को बाहर निकालना शुरू किया। कई ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने का प्रयास किया, जो मानवीय संवेदनशीलता का बड़ा उदाहरण है। सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक टीमें भी

घटनास्थल पर पहुंचीं और राहत कार्य को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया गया।

घायलों को तत्काल बंजार के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल यात्रियों को कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस अधीक्षक Madan Lal Kaushal ने पुष्टि करते हुए बताया कि हादसे में चार लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि उन्नीस घायलों का इलाज जारी है। कुछ घायलों की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है।

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि तेज गति और पहाड़ी मार्ग के खतरनाक मोड़ों पर लापरवाही इस हादसे का मुख्य कारण हो सकती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के हर पहलू की गहन जांच की जा रही है। इसमें चालक की स्थिति, वाहन की तकनीकी हालत और सड़क की भौगोलिक परिस्थितियों की भी जांच शामिल है।

हादसे में घायल हुए यात्रियों में देश के विभिन्न राज्यों के लोग शामिल हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वाहन में सवार लोग पर्यटक थे या यात्रा पर निकले हुए थे। घायलों में कुरुक्षेत्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर के निवासी शामिल हैं। इनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जिससे हादसे की संवेदनशीलता और अधिक बढ़ जाती है। प्रशासन द्वारा सभी घायलों के परिजनों को सूचना दी जा रही है और उनके इलाज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

इस घटना के बाद प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय वाहन चालकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन चलाते समय नियंत्रित गति, सतर्कता और नियमों का पालन अनिवार्य बताया गया है। अधिकारियों का कहना है कि थोड़ी सी लापरवाही भी इस तरह के भीषण हादसों का कारण बन सकती है, इसलिए जागरूकता और जिम्मेदारी बेहद जरूरी है।

यह हादसा एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्राकृतिक सुंदरता के बीच बसे पहाड़ी रास्ते जितने आकर्षक होते हैं, उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं। हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश की वादियों का आनंद लेने पहुंचते हैं, लेकिन सुरक्षित यात्रा के नियमों की अनदेखी कई बार ऐसी त्रासद घटनाओं को जन्म दे देती है।

फिलहाल प्रशासन राहत और बचाव कार्य के साथ-साथ घायलों के इलाज पर पूरा ध्यान दे रहा है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह दुर्घटना न केवल प्रभावित परिवारों के लिए अपूरणीय क्षति है, बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन हर परिस्थिति में अनिवार्य है।

# पेट्रोल-डीजल के बाद अब सीएनजी महंगी, पश्चिम एशिया संकट का सीधा असर, आम आदमी पर बढ़ा बोझ

New Delhi। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव का असर अब भारत के ऊर्जा बाजार पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद अब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी भी महंगी हो गई है। गैस वितरण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी Torrent Gas द्वारा विभिन्न राज्यों में दरों में वृद्धि किए जाने के बाद इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं और परिवहन क्षेत्र पर पड़ने लगा है। लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों ने महंगाई के दबाव को और गहरा कर दिया है, जिससे आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ना तय माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में सीएनजी की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यहां पहले जहां सीएनजी 93.50 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास उपलब्ध थी, अब इसे बढ़ाकर 96.25 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। यानी प्रति किलोग्राम लगभग 2.75 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जो रोजमर्रा के आवागमन के लिए सीएनजी वाहनों पर निर्भर हैं। इसी प्रकार राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी सीएनजी की कीमतों में करीब 2.50 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है, जिससे वहां दरें बढ़कर लगभग 95.50 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं।

केवल उत्तर प्रदेश और राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी सीएनजी के दाम बढ़े हैं। पंजाब में कीमतें लगभग 94.25 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं, जबकि तेलंगाना में यह आंकड़ा करीब 99 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास दर्ज किया गया है। गुजरात में सीएनजी लगभग 85.17 रुपये प्रति किलोग्राम, महाराष्ट्र में करीब 94.50 रुपये प्रति किलोग्राम और तमिलनाडु में लगभग 94 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। इन

बढ़ी हुई दरों से स्पष्ट है कि यह असर क्षेत्रीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर महसूस किया जा रहा है।

ऊर्जा बाजार में यह उछाल ऐसे समय में आया है, जब हाल ही में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी भारी वृद्धि की गई थी। पिछले कुछ महीनों में व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में पांच बार बढ़ोतरी हो चुकी है, जिसमें हालिया वृद्धि लगभग 218 रुपये तक की रही। वहीं घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी 7 मार्च 2026 को 60 रुपये प्रति सिलेंडर का इजाफा किया गया था। इससे घरेलू बजट पर पहले से ही दबाव बना हुआ है, जो अब सीएनजी महंगी होने से और बढ़ गया है।

निजी क्षेत्र की अन्य कंपनियों ने भी ईंधन कीमतों में वृद्धि की है। Shell India और Nayara Energy जैसी कंपनियों ने हाल के दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। बेंगलुरु जैसे शहर में पेट्रोल की कीमत में 7.41 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि नायरा एनर्जी ने पेट्रोल में 5 रुपये और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर तक वृद्धि की है। इससे परिवहन लागत में बढ़ोतरी होना तय है, जिसका असर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर भी पड़ेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव, कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति संबंधी अनिश्चितताओं के कारण भारत जैसे आयात-निर्भर देश पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। ऊर्जा कीमतों में वृद्धि का प्रभाव केवल ईंधन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह महंगाई के रूप में पूरे आर्थिक ढांचे को प्रभावित करता है।

हालांकि, बढ़ती कीमतों के दबाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ राहत देने की कोशिश की है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) में कटौती की है। पेट्रोल पर यह शुल्क 13 रुपये से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल पर 10 रुपये से घटाकर शून्य कर दिया गया है। सरकार का यह कदम उपभोक्ताओं को आंशिक राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता के कारण कीमतों पर पूरी तरह नियंत्रण अभी भी चुनौती बना हुआ है।

कुल मिलाकर, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बाद अब सीएनजी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने आम जनता की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। परिवहन से लेकर घरेलू खर्च तक, हर स्तर पर इसका असर महसूस किया जा रहा है। आने वाले समय में यदि अंतरराष्ट्रीय हालात में सुधार नहीं होता है, तो ईंधन कीमतों में और बढ़ोतरी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, जो देश की अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

# प्रेम विवाद बना खूनी संग्राम, उन्नाव में कुल्हाड़ी से हत्या से दहला गांव

उन्नाव जिले के बिहार थाना क्षेत्र के बैजुआमऊ गांव में शनिवार का दिन उस समय भयावह त्रासदी में बदल गया, जब प्रेम-प्रसंग को लेकर दो परिवारों के बीच चला आ रहा तनाव अचानक हिंसा की आग में भड़क उठा और एक निर्दोष व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह घटना न केवल एक परिवार को उजाड़ गई, बल्कि पूरे गांव को दहशत और शोक के माहौल में डुबो गई। मामूली विवाद से शुरू हुआ यह टकराव कुछ ही देर में इतना उग्र हो गया कि गुस्से में अंधे एक युवक ने कुल्हाड़ी से हमला कर प्रेमी के पिता की निर्मम हत्या कर दी, जबकि परिवार के तीन अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, गांव निवासी राजकुमार की बेटी मालती और पड़ोस में रहने वाले पुत्तीलाल के बेटे पवन के बीच लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों एक-दूसरे को चाहते थे, लेकिन उनके इस रिश्ते को लड़की के परिवार की मंजूरी नहीं थी। शनिवार की दोपहर करीब साढ़े बारह बजे मालती ने सामाजिक बंधनों और परिवार के विरोध की परवाह किए बिना अपनी मर्जी से प्रेमी पवन के घर जाने का फैसला कर लिया। यह कदम लड़की के परिवार को नागवार गुजरा और उनके भीतर आक्रोश की चिंगारी भड़क उठी।

शाम ढलते-ढलते यही आक्रोश हिंसा में तब्दील हो गया। मालती के परिजन गुस्से से भरे पवन के घर पहुंचे और वहां पहुंचते ही दोनों परिवारों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते माहौल इतना गर्म हो गया कि कहासुनी गाली-गलौज में बदल गई और फिर मारपीट शुरू हो गई। गांव के लोग इस झगड़े को शांत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन हालात तेजी से बेकाबू होते चले गए।

इसी दौरान आरोप है कि मालती के भाई दीपक ने अपना आपा खो दिया और पास में रखी कुल्हाड़ी उठाकर पवन के पिता पुत्तीलाल (50 वर्ष) के सिर पर जोरदार वार कर दिया। वार इतना घातक था कि पुत्तीलाल

मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े। उनके सिर से बहते खून और गंभीर चोटों के कारण कुछ ही पलों में उनकी सांसें थम गईं। इस खौफनाक मंजर को देखकर वहां मौजूद लोग सन्न रह गए और पूरे इलाके में चीख-पुकार मच गई।

इस खूनी संघर्ष में पुत्तीलाल के परिवार के अन्य सदस्य भी बुरी तरह घायल हो गए। सुनीता, अमन और राजेश्वरी को गंभीर चोटें आईं और उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीघापुर पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कुछ घायलों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी है। क्षेत्राधिकारी बीघापुर मधुपनाथ मिश्रा के अनुसार, इस मामले में तीन नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। पुत्तीलाल के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और हर कोई इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि यदि समय रहते दोनों परिवारों के बीच संवाद और समझदारी से मामला सुलझा लिया जाता, तो शायद यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन एक पल का गुस्सा और सामाजिक दबाव ने एक जिंदगी छीन ली और कई लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया।

यह घटना समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है कि रिश्तों और भावनाओं को लेकर बढ़ती असहिष्णुता किस तरह भयावह परिणाम दे सकती है। प्रेम-प्रसंग जैसे संवेदनशील मुद्दों को समझदारी और धैर्य से सुलझाने के बजाय हिंसा का रास्ता चुनना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह इंसानियत के मूल्यों के भी खिलाफ है। फिलहाल पुलिस मामले की तह तक पहुंचने में जुटी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक समाज में ऐसे विवाद खून-खराबे में बदलते रहेंगे।

# बाजार में भारी गिरावट, एयरटेल को सबसे बड़ा झटका; निवेशकों की घबराहट से टॉप कंपनियों की वैल्यू डूबी

नई दिल्ली। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक तनाव और घरेलू बाजार में कमजोर निवेशक विश्वास के चलते बीते सप्ताह शेयर बाजार पर भारी दबाव देखने को मिला। पूरे सप्ताह बाजार में उतार-चढ़ाव का माहौल बना रहा, लेकिन अंततः गिरावट का रुख हावी रहा। इसका सीधा असर देश की दिग्गज कंपनियों के बाजार पूंजीकरण पर पड़ा, जहां शीर्ष 10 में शामिल 6 कंपनियों के संयुक्त मार्केट कैप में करीब 64,734 करोड़ रुपये की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि फिलहाल बाजार में निवेशकों का भरोसा डगमगाया हुआ है और वे सतर्क रुख अपनाए हुए हैं।

सप्ताह के दौरान बीएसई सेंसेक्स 263.67 अंकों यानी 0.35 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी में 106.5 अंकों यानी 0.46 प्रतिशत की कमजोरी दर्ज की गई। यह लगातार छठा सप्ताह रहा जब बाजार लाल निशान में बंद हुआ, जो निवेशकों की बढ़ती चिंता और वैश्विक संकेतों के प्रभाव को दर्शाता है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं और सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं।

इस गिरावट का सबसे ज्यादा असर दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारती एयरटेल पर पड़ा, जिसका बाजार पूंजीकरण लगभग 29,993 करोड़ रुपये घटकर करीब 10.20 लाख करोड़ रुपये रह गया। यह गिरावट इस सप्ताह की सबसे बड़ी गिरावटों में से एक रही और इससे कंपनी के निवेशकों को बड़ा झटका लगा। एयरटेल के शेयरों में आई इस कमजोरी ने पूरे टेलीकॉम सेक्टर पर भी दबाव बनाया।

वहीं बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की प्रमुख

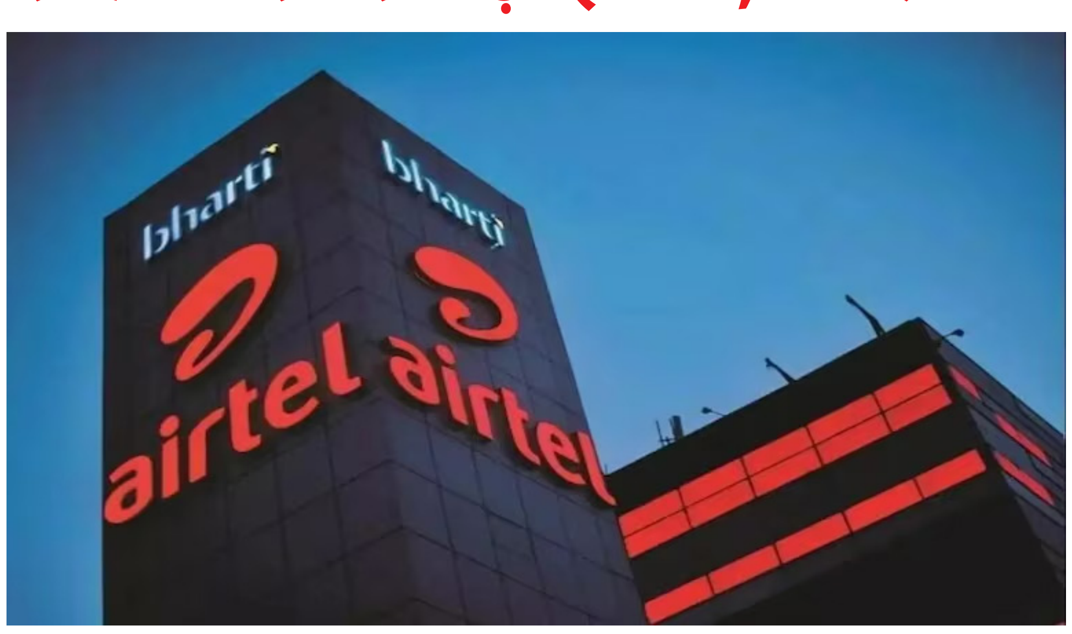


कंपनियां भी इस गिरावट से अछूती नहीं रहीं। आईसीआईसीआई बैंक के बाजार मूल्य में 12,845 करोड़ रुपये की कमी आई, जिससे उसका कुल मार्केट कैप घटकर लगभग 8.70 लाख करोड़ रुपये रह गया। इसी तरह बजाज फाइनेंस को 11,169 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जबकि एचडीएफसी बैंक के बाजार पूंजीकरण में 7,822 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई। उपभोक्ता क्षेत्र की बड़ी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर को 2,349 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, वहीं भारतीय स्टेट बैंक के मार्केट कैप में 553 करोड़ रुपये की मामूली कमी आई। हालांकि, बाजार में आई इस व्यापक गिरावट के बीच कुछ कंपनियों ने मजबूती का प्रदर्शन भी किया और निवेशकों को राहत दी। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का बाजार मूल्य 22,359 करोड़ रुपये बढ़कर 8.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसी तरह इन्फोसिस ने भी 12,374 करोड़ रुपये की बढ़त दर्ज की। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टुब्रो में 6,575 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ, जबकि देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 3,518 करोड़ रुपये की बढ़त के साथ अपनी शीर्ष स्थिति बरकरार रखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का कुल बाजार पूंजीकरण 18.28 लाख करोड़ रुपये पर बना रहा, जो इसे देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाए रखता है।

बाजार की इस गिरावट के पीछे कई वैश्विक और घरेलू कारक एक साथ काम करते नजर आए। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता पैदा की, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा। कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी ने निवेशकों की चिंता को और बढ़ाया, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ने और आर्थिक दबाव बढ़ने की आशंका रहती है। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा लगातार की जा रही बिकवाली ने बाजार पर अतिरिक्त दबाव बनाया। घरेलू स्तर पर रुपये की कमजोरी और महंगाई से जुड़ी चिंताओं ने भी निवेशकों के मनोबल को प्रभावित किया। हालांकि सप्ताह के बीच में कुछ सकारात्मक संकेत भी देखने को मिले, लेकिन वे बाजार को स्थायी राहत देने में सफल नहीं हो सके। कुल मिलाकर बाजार का रुख नकारात्मक ही बना रहा और निवेशकों ने सतर्कता बनाए रखी।

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में बाजार की दिशा काफी हद तक वैश्विक परिस्थितियों, कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी निवेशकों के रुख पर निर्भर करेगी। जब तक इन कारकों में स्थिरता नहीं आती, तब तक बाजार में उतार-चढ़ाव का दौर जारी रहने की संभावना है। फिलहाल निवेशकों को सोच-समझकर और दीर्घकालिक रणनीति के तहत निवेश करने की सलाह दी जा रही है, ताकि इस अस्थिर दौर में जोखिम को कम किया जा सके।

# खड़े टैंकर से टकराई तेज रफ्तार बोलेरो, बरेली में चीख-पुकार के बीच 5 की मौत, कई जिंदगी से जूझ रहे

बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रविवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जिसने कुछ ही क्षणों में खुशियों से भरी एक यात्रा को मातम में बदल दिया। सीबीगंज थाना क्षेत्र के परधोली गांव के पास तेज रफ्तार से दौड़ रही एक बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े टैंकर से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और वाहन के अंदर बैठे लोग बुरी तरह फंस गए। इस भयावह दुर्घटना में पांच लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक मासूम बच्चे समेत करीब आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना भीषण था कि टक्कर की आवाज दूर-दूर तक सुनाई

दी और आसपास के लोग दहशत में मौके की ओर दौड़ पड़े। बोलेरो की हालत ऐसी हो गई थी कि उसमें फंसे लोगों को बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो गया। कई लोग अंदर ही दबे हुए थे और दर्द से कराह रहे थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर थी कि शवों को बाहर निकालने के लिए वाहन को काटना पड़ा। इस दौरान मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य को तेज किया। घायलों को तत्काल नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कुछ घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतकों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में हादसे का मुख्य कारण तेज रफ्तार और सड़क किनारे खड़ा टैंकर माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह टैंकर पहले हुए एक अन्य हादसे के बाद से वहीं खड़ा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक, शनिवार को भी इसी स्थान पर एक टैंकर और रोडवेज बस के बीच टक्कर हुई थी, जिसके बाद दुर्घटनाग्रस्त टैंकर को हटाया नहीं गया। रविवार को वही टैंकर एक और बड़े हादसे की वजह बन गया। हादसे के समय बोलेरो अनियंत्रित होकर सीधे टैंकर में जा घुसी और इसके तुरंत बाद पीछे से आ रही एक बाइक भी बोलेरो से टकरा गई, जिससे स्थिति और भयावह हो गई। यह पूरी घटना कुछ ही सेकंड में घटित हो गई, लेकिन इसके परिणाम बेहद दर्दनाक रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन समय रहते सड़क से टैंकर को हटवा देता, तो शायद यह हादसा टल सकता था और कई जिंदगियां बचाई जा सकती थीं।

# अमूल ने रचा इतिहास, एक लाख करोड़ के पार पहुंचा कारोबार

## किसानों की ताकत से डेयरी सेक्टर को मिली नई उड़ान

नई दिल्ली। भारत के डेयरी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए देश की अग्रणी ब्रांड अमूल ने वित्त वर्ष 2025-26 में अपने ब्रांड टर्नओवर को एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचाकर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। यह केवल एक व्यावसायिक सफलता नहीं, बल्कि भारत के सहकारी मॉडल, किसानों की मेहनत और उपभोक्ताओं के भरोसे की एक बड़ी जीत के रूप में सामने आई है। लगातार बढ़ती मांग, व्यापक उत्पाद श्रृंखला और मजबूत वितरण नेटवर्क के दम पर अमूल ने न सिर्फ अपने कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, बल्कि भारतीय एफएमसीजी सेक्टर में अपनी स्थिति को और अधिक सुदृढ़ कर लिया।

गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (GCMMF), जो अमूल ब्रांड का विपणन करती है, के अनुसार कंपनी का ब्रांड टर्नओवर इस वित्त वर्ष में करीब 11 प्रतिशत बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया। पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा लगभग 90,000 करोड़ रुपये के आसपास था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अमूल ने एक ही वर्ष में तेज रफ्तार से विकास करते हुए बाजार में अपनी पकड़ को और मजबूत किया है। इसी अवधि में GCMMF का स्वयं का कारोबार भी 11.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 65,911 करोड़ रुपये से बढ़कर 73,450 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

अमूल की इस सफलता के पीछे उसकी विविध और विस्तृत उत्पाद श्रृंखला एक प्रमुख कारण रही है। वर्तमान में कंपनी के पास 1,200 से अधिक उत्पादों का विशाल पोर्टफोलियो है, जिसमें दूध, मक्खन, पनीर, घी, आइसक्रीम, दही, छाछ और कई अन्य डेयरी उत्पाद शामिल हैं। बदलती उपभोक्ता जरूरतों के अनुरूप नए उत्पादों की लगातार लॉन्चिंग और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने से अमूल ने हर वर्ग के उपभोक्ताओं के बीच अपनी मजबूत पहचान बनाई है। यही वजह है कि शहरों से लेकर गांवों तक अमूल के उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है।

कंपनी की सफलता में उसका मजबूत और विस्तृत वितरण नेटवर्क भी अहम भूमिका निभा रहा है। देश के कोने-कोने तक फैला इसका सप्लाई सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि ताजे और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद समय पर उपभोक्ताओं तक पहुंचें। इसके साथ ही डिजिटल तकनीक और आधुनिक लॉजिस्टिक्स का उपयोग कर कंपनी ने अपने संचालन को और अधिक प्रभावी बनाया है, जिससे लागत में कमी और दक्षता में वृद्धि हुई है।

अमूल अब केवल घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान मजबूत करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। GCMMF के प्रबंध निदेशक जयन मेहता के अनुसार, कंपनी वैश्विक बाजारों में विस्तार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि इस विस्तार का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे। तकनीक और नवाचार के माध्यम से डेयरी क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के प्रयास भी तेज किए जा रहे हैं।

# शादी के छह महीने बाद टूटा रिश्ता, पत्नी के बिछड़ने का दर्द न सह सका युवक; मुरादाबाद में फांसी लगाकर दी जान

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां वैवाहिक जीवन में आई दरार ने एक युवक को इस कदर तोड़ दिया कि उसने अपनी जिंदगी ही समाप्त कर ली। मझोला थाना क्षेत्र की कांशीराम कॉलोनी में रहने वाले 26 वर्षीय राजमिस्त्री अनेक पाल ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उसकी शादी महज छह महीने पहले ही हुई थी, लेकिन पत्नी के मायके चले जाने और वापस न लौटने से वह गहरे मानसिक तनाव में चला गया था। इसी अवसाद में उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया।

घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है और मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार, अनेक पाल अपने पिता भूरे के साथ कांशीराम कॉलोनी में रहता था। छह महीने पहले ही उसका विवाह रामपुर जिले के टांडा क्षेत्र की रहने वाली मधु के साथ बड़े ही धूमधाम से हुआ था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ समय बाद पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी नाराज होकर अपने मायके चली गई और फिर वापस नहीं लौटी।

परिजनों के अनुसार, अनेक पाल लगातार अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश कर रहा था। वह कई बार उसे वापस लाने के लिए प्रयास करता रहा, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। पत्नी की बेरुखी और रिश्ते में आई दूरी ने उसे अंदर ही अंदर तोड़ दिया। धीरे-धीरे वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा और गहरे अवसाद में चला गया। परिवार के लोग भी

उसकी हालत को लेकर चिंतित थे, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वह इतना बड़ा कदम उठा लेगा। शुक्रवार की देर रात अनेक पाल ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब उसके पिता उसे जगाने के लिए कमरे के बाहर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कई बार आवाज देने के बावजूद जब दरवाजा नहीं खुला, तो उन्हें अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों और रिश्तेदारों की मदद से दरवाजा तोड़ा। अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए—अनेक पाल का शव फंदे से लटका हुआ था।

इस दर्दनाक मंजर को देखकर पिता और परिवार के अन्य सदस्य बेसुध हो गए। घर में चीख-पुकार मच गई और देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में यह खबर फैल गई। जवान बेटे की मौत से पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। वे बार-बार यही कहते नजर आए—"क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने बेटे की शादी कराई थी?" परिवार के अन्य सदस्य भी गहरे सदमे में हैं और पूरे इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है।

घटना की सूचना मिलते ही मझोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही कमरे से साक्ष्य भी जुटाए गए हैं, ताकि घटना के हर पहलू की जांच की जा सके।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसे संदिग्ध मानते हुए हर एंगल से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी और उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह घटना समाज के सामने कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है। वैवाहिक जीवन में छोटी-छोटी बातों पर बढ़ते विवाद और संवादहीनता किस तरह एक व्यक्ति को मानसिक रूप से तोड़ सकती है, यह इसका उदाहरण है। रिश्तों में आई दरार को समय रहते समझदारी और बातचीत से सुलझाने की जरूरत होती है, वरना इसके परिणाम बेहद भयावह हो सकते हैं।

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, वहीं मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक ओर जहां छह महीने पहले घर में शादी की खुशियां थीं, वहीं आज उसी घर में मातम पसरा है। यह घटना न केवल एक परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है, बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है कि भावनात्मक तनाव और रिश्तों की उलझनों को नजरअंदाज करना कभी-कभी जानलेवा साबित हो सकता है।

# प्राइमरी मार्केट में सीमित हलचल, इस सप्ताह दो आईपीओ खुलेंगे; एक कंपनी की ही होगी लिस्टिंग

नई दिल्ली। शेयर बाजार में जारी अस्थिरता और वैश्विक स्तर पर बढ़ते आर्थिक व भू-राजनीतिक दबाव के बीच इस सप्ताह प्राइमरी मार्केट में हलचल बेहद सीमित रहने के संकेत मिल रहे हैं। 6 अप्रैल से शुरू हो रहे कारोबारी सप्ताह में निवेशकों के लिए केवल दो नए आईपीओ खुलने जा रहे हैं, जबकि सेकेंडरी मार्केट में महज एक कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग होने की संभावना है। मौजूदा परिस्थितियों में यह परिदृश्य साफ तौर पर दर्शाता है कि कंपनियां फिलहाल बड़े दांव लगाने से बच रही हैं और निवेशकों की सतर्कता के चलते पूंजी जुटाने के लिए छोटे और सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख कर रही हैं।

सप्ताह की शुरुआत एक छोटे लेकिन दिलचस्प इश्यू से होने जा रही है। 6 अप्रैल को सेफ्टी कंट्रोल एंड डिवाइसेज कंपनी अपना लगभग 48 करोड़ रुपये का आईपीओ लेकर बाजार में उतर रही है। यह इश्यू 8 अप्रैल तक निवेशकों के लिए खुला रहेगा, जिसमें खुदरा निवेशक, उच्च निवल मूल्य वाले निवेशक और अन्य श्रेणियों के प्रतिभागी अपनी बोली लगा सकेंगे। कंपनी ने प्रति शेयर 75 से 80 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है, जो इसे अपेक्षाकृत किफायती बनाता है। न्यूनतम 1,600 शेयरों के लॉट साइज के साथ यह इश्यू खास तौर पर उन निवेशकों को आकर्षित कर सकता है, जो एसएमई सेगमेंट में निवेश के अवसर तलाश रहे हैं। इस आईपीओ के बंद होने के बाद कंपनी के शेयरों की संभावित लिस्टिंग 13 अप्रैल को बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर हो सकती है।

सप्ताह के अंत में प्राइमरी मार्केट में एक अलग तरह का अवसर देखने को मिलेगा, जब 10 अप्रैल को प्रॉपशेयर सेलेस्टिया अपना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) आधारित आईपीओ लॉन्च करेगी। यह इश्यू 16 अप्रैल तक खुला रहेगा और इसके जरिए कंपनी लगभग 244.65 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। इस इश्यू की खासियत यह है कि यह पारंपरिक शेयर आईपीओ से अलग है और निवेशकों को रियल एस्टेट सेक्टर में भागीदारी का मौका देता है। हालांकि इसका प्राइस बैंड 10 लाख से 10.50 लाख रुपये प्रति यूनिट रखा गया है, जो इसे आम खुदरा निवेशकों की पहुंच से बाहर करता है और मुख्य रूप से उच्च आय वर्ग के निवेशकों के लिए उपयुक्त बनाता है। कंपनी द्वारा कुल 2,330 यूनिट्स जारी किए जाएंगे और इसकी संभावित लिस्टिंग 24 अप्रैल को बीएसई पर मानी जा रही है।

जहां एक ओर प्राइमरी मार्केट में सीमित गतिविधि देखने को मिल रही है, वहीं सेकेंडरी मार्केट में भी इस सप्ताह नई एंट्री बेहद कम रहने वाली है। केवल विविड इलेक्ट्रोमेच कंपनी के शेयर 7 अप्रैल को एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने की संभावना है। यह इस सप्ताह की एकमात्र लिस्टिंग होगी, जिससे निवेशकों के पास नए स्टॉक्स में निवेश के अवसर भी सीमित रहेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा बाजार परिस्थितियां इस सुस्ती की मुख्य वजह हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी और घरेलू स्तर पर महंगाई व रुपये की कमजोरी जैसे कारकों ने बाजार में अनिश्चितता को बढ़ा दिया है। ऐसे माहौल में कंपनियां बड़े मेनबोर्ड आईपीओ लाने से बच रही हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त सब्सक्रिप्शन और बेहतर वैल्यूएशन मिलने को लेकर संदेह बना हुआ है। इसके विपरीत, एसएमई और वैकल्पिक निवेश साधनों के माध्यम से पूंजी जुटाने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। छोटे आकार के आईपीओ कम जोखिम वाले माने जाते हैं और मौजूदा परिस्थितियों में इन्हें निवेशकों से अपेक्षाकृत बेहतर प्रतिक्रिया मिल सकती है। साथ ही, REIT जैसे विकल्प निवेशकों को विविधीकरण का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वे पारंपरिक इक्विटी बाजार के उतार-चढ़ाव से कुछ हद तक बच सकते हैं।

निवेशकों के लिए यह समय बेहद सावधानी बरतने का है। विशेषज्ञों की सलाह है कि किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल, वित्तीय प्रदर्शन, बाजार में उसकी स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का गहन विश्लेषण करना आवश्यक है। बाजार में भले ही गतिविधियां सीमित हों, लेकिन सही रणनीति और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाकर निवेशक इस दौर में भी अच्छे अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।

कुल मिलाकर, यह सप्ताह प्राइमरी मार्केट के लिहाज से भले ही शांत नजर आ रहा हो, लेकिन इसके भीतर छिपे संकेत यह दर्शाते हैं कि बाजार एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। आने वाले समय में यदि वैश्विक परिस्थितियां स्थिर होती हैं और निवेशकों का भरोसा लौटता है, तो प्राइमरी मार्केट में फिर से तेजी और बड़े आईपीओ की वापसी देखी जा सकती है। फिलहाल निवेशकों को धैर्य और समझदारी के साथ कदम बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि यही रणनीति इस अनिश्चित दौर में सबसे सुरक्षित साबित हो सकती है।

# ग्रीन बजट के जरिए राजधानी में पर्यावरणीय बदलाव की बड़ी पहल, हर विभाग को सौंपी गई जिम्मेदारी

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली, जो वर्षों से प्रदूषण, जल संकट और अनियोजित शहरीकरण जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है, अब एक बड़े पर्यावरणीय बदलाव की ओर कदम बढ़ा रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत किए गए ग्रीन बजट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार अब विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की दिशा में ठोस और व्यापक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। कुल 1,03,700 करोड़ रुपये के बजट में से 22,236 करोड़ रुपये यानी लगभग 21.44 प्रतिशत हिस्सा हरित योजनाओं के लिए निर्धारित किया जाना इस बात का संकेत है कि पर्यावरण संरक्षण अब केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि शासन की प्राथमिक नीति बन चुका है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बजट को पेश करते हुए जिस "क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली" विजन की बात की, वह केवल एक नारा नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक सोच का प्रतिबिंब है। राजधानी को प्रदूषण मुक्त, जल-संरक्षित और हरित बनाने के लिए सरकार ने 17 विभागों को जिम्मेदारी सौंपकर एक समन्वित मॉडल तैयार किया है। यह मॉडल इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि अब पर्यावरणीय सुधार केवल एक विभाग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शासन के हर हिस्से में इसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

इस ग्रीन बजट का सबसे बड़ा हिस्सा दिल्ली जल बोर्ड को दिया गया है, जिसे 6,485 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह राशि मुख्य रूप से यमुना नदी की सफाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के विस्तार और जल पुनर्चक्रण परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी। यमुना की स्थिति लंबे समय से चिंता का विषय रही है और इसे साफ करने के लिए कई योजनाएं बनीं, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। इस बार सरकार ने बड़े पैमाने पर निवेश कर यह संकेत दिया है कि जल प्रबंधन को लेकर अब गंभीर और परिणामोन्मुखी प्रयास किए जाएंगे। परिवहन क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की तैयारी है। 4,758 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ सरकार इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाने पर जोर दे रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है, और इस दिशा में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यदि यह योजना प्रभावी रूप से लागू होती है, तो आने वाले वर्षों में दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखा जा सकता है।

लोक निर्माण विभाग को 3,350 करोड़ रुपये देकर सड़कों पर धूल नियंत्रण, ग्रीन कॉरिडोर और हरित बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राजधानी में धूल प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है, जिसे नियंत्रित करने के लिए आधुनिक तकनीकों और योजनाओं की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इसके साथ ही योजना विभाग को 2,350 करोड़ रुपये देकर यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी परियोजनाओं की रूपरेखा वैज्ञानिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ तैयार की जाए।

शहरी विकास विभाग और दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (DUSIB) को मिलाकर 2,273 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिससे झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ हरित विकास को बढ़ावा दिया जा सके। बिजली विभाग को 1,410 करोड़ रुपये आवंटित कर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, खासकर सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई गई है। इससे न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी।

पर्यावरण विभाग को 558 करोड़ रुपये प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिए गए हैं, जिसमें एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, प्रदूषण नियंत्रण उपायों और जागरूकता अभियानों पर खर्च किया जाएगा। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को 305 करोड़ रुपये जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए दिए गए हैं, जबकि विकास विभाग को 258 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में हरित विकास और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए आवंटित किए गए हैं।

वन विभाग को 181 करोड़ रुपये देकर हरित क्षेत्र बढ़ाने, वृक्षारोपण और जैव विविधता संरक्षण पर जोर दिया गया है। पर्यटन विभाग को 102 करोड़ रुपये देकर इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। शिक्षा विभाग को 100 करोड़ रुपये देकर स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील बन सकें। इसके अलावा उद्योग, स्वास्थ्य, राजस्व, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा विभागों को भी बजट आवंटित कर यह सुनिश्चित किया गया है कि पर्यावरणीय सोच हर क्षेत्र में समाहित हो। यह व्यापक दृष्टिकोण इस ग्रीन बजट की सबसे बड़ी विशेषता है, जो इसे पारंपरिक बजट से अलग बनाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन योजनाओं को सही तरीके से लागू किया गया, तो दिल्ली आने वाले वर्षों में एक मॉडल ग्रीन सिटी के रूप में उभर सकती है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन, विभागों के बीच समन्वय और निगरानी तंत्र की मजबूती इस पूरी पहल की सफलता तय करेगी। कुल मिलाकर, दिल्ली का यह ग्रीन बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि एक व्यापक दृष्टि और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि सरकार अब विकास को केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन के साथ आगे बढ़ना चाहती है।

# विदेशी निवेशकों की बड़ी निकासी से डगमगाया बाजार अप्रैल की शुरुआत में ही 19,837 करोड़ रुपये बाहर

नई दिल्ली। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार पर विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली का दबाव और गहराता जा रहा है। अप्रैल 2026 की शुरुआत ही बाजार के लिए झटके भरी रही, जब महज दो कारोबारी सत्रों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने 19,837 करोड़ रुपये की भारी निकासी कर दी। इस तेज बिकवाली ने निवेशकों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है तथा बाजार के रुख को अस्थिर बना दिया है।

यह निकासी ऐसे समय में सामने आई है, जब मार्च 2026 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजार से रिकॉर्ड स्तर पर 1.17 लाख करोड़ रुपये की पूंजी बाहर निकाली थी। यह अब तक की सबसे बड़ी मासिक निकासी मानी जा रही है और इससे बाजार में गहरी कमजोरी देखने को मिली थी। इसके विपरीत फरवरी 2026 में विदेशी निवेशकों ने 22,615 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जो पिछले 17 महीनों का उच्चतम स्तर था। लेकिन मार्च और अप्रैल की शुरुआत में आई यह तेज गिरावट यह संकेत देती है कि निवेशकों का भरोसा फिलहाल डगमगाया हुआ है और वे जोखिम से बचने की रणनीति अपना रहे हैं।

डिपॉजिटरी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2026 में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की कुल निकासी का आंकड़ा लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। केवल अप्रैल के शुरुआती दो

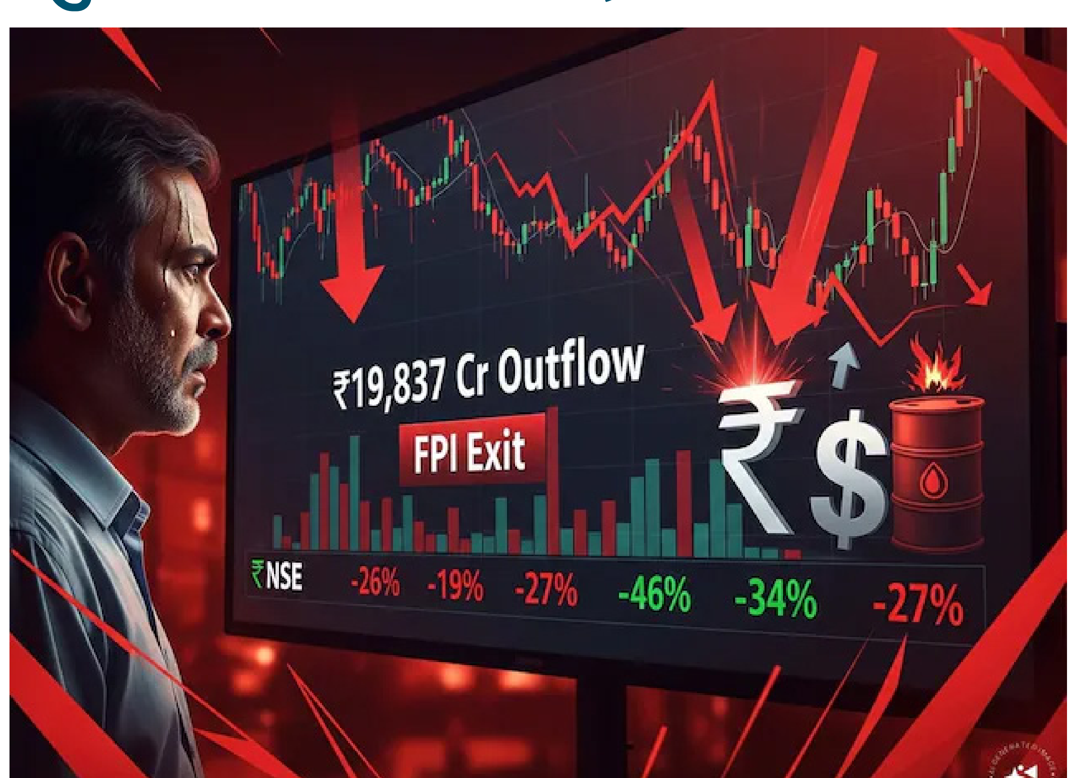


दिनों में ही कैश मार्केट में बड़े पैमाने पर इक्विटी की बिकवाली दर्ज की गई, जिससे बाजार पर दबाव और बढ़ गया। इस लगातार निकासी ने घरेलू निवेशकों के मनोबल को भी प्रभावित किया है और बाजार में उतार-चढ़ाव का दौर तेज हो गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी निवेशकों की इस आक्रामक बिकवाली के पीछे कई वैश्विक और घरेलू कारण एक साथ काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध जैसी स्थिति ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है। इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों का 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जाना भारत जैसे आयातक देश के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि इससे महंगाई और चालू खाता घाटा बढ़ने की आशंका रहती है।

रुपये की कमजोरी भी निवेशकों के लिए एक बड़ा कारक बनकर उभरी है। बाजार विशेषज्ञ वी.के. विजयकुमार के अनुसार, मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के चलते भारतीय रुपया अब तक लगभग 4 प्रतिशत तक कमजोर हो चुका है और इसके और गिरने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में विदेशी निवेशक अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय बाजार से पूंजी निकाल रहे हैं और कम जोखिम वाले विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं।

इसके अलावा अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी ने भी विदेशी निवेशकों के फैसलों को प्रभावित किया है। विश्लेषक हिमांशु श्रीवास्तव के अनुसार, जब विकसित देशों में फिक्स्ड-इनकम साधनों पर बेहतर रिटर्न मिलने लगता है, तो वैश्विक निवेशक इक्विटी जैसे जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाकर सुरक्षित परिसंपत्तियों में निवेश बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि भारतीय बाजार से पूंजी का प्रवाह बाहर की ओर बढ़ रहा है।

हालांकि इस लगातार बिकवाली के बीच कुछ सकारात्मक संकेत भी उभर रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी निवेशकों की निकासी के चलते भारतीय शेयर बाजार का वैल्यूएशन अब संतुलित स्तर की ओर बढ़ रहा है। कई सेक्टरों में कीमतों में आई गिरावट के कारण दीर्घकालिक निवेशकों के लिए नए अवसर भी बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए निवेशकों को सतर्कता और समझदारी से निर्णय लेने की जरूरत होगी।

आने वाले समय में बाजार की दिशा काफी हद तक वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। यदि पश्चिम एशिया में तनाव कम होता है, कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता आती है और रुपये की स्थिति मजबूत होती है, तो विदेशी निवेशकों की वापसी संभव है। फिलहाल बाजार अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है और निवेशकों को हर कदम सोच-समझकर उठाने की सलाह दी जा रही है, ताकि इस उतार-चढ़ाव भरे माहौल में जोखिम को नियंत्रित किया जा सके।

# सप्ताहांत की नरमी के बावजूद तेजी की धार, सर्राफा बाजार में निवेशकों का भरोसा बरकरार

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार ने सप्ताह के अंतिम कारोबारी सत्र में भले ही हल्की नरमी का संकेत दिया हो, लेकिन पूरे सप्ताह के रुझान पर नजर डालें तो सोना और चांदी दोनों ही धातुओं ने मजबूती का परिचय दिया है। यह परिदृश्य निवेशकों की उस मनोवृत्ति को दर्शाता है, जिसमें अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के बावजूद कीमती धातुओं को सुरक्षित निवेश के रूप में प्राथमिकता दी जा रही है। सप्ताहांत पर कीमतों में आई मामूली गिरावट को बाजार विशेषज्ञ एक सामान्य तकनीकी सुधार मान रहे हैं, न कि किसी बड़े ट्रेंड के बदलने का संकेत।

सप्ताह के आखिरी दिन देश के प्रमुख बाजारों में 24 कैरेट सोने की कीमतें लगभग 1,50,930 से 1,51,080 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में बनी रहीं। इसी तरह 22 कैरेट सोना 1,38,350 से 1,38,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच कारोबार करता नजर आया। कीमतों में यह सीमित गिरावट उस तेजी के बाद आई है, जो पूरे सप्ताह के दौरान देखने को मिली थी। बाजार के जानकारों के अनुसार, ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली के चलते यह हल्की नरमी आई है, जो किसी भी तेजी वाले बाजार में स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाती है।

दूसरी ओर चांदी ने सप्ताहांत पर अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया और मामूली मजबूती के साथ लगभग 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर तक पहुंच गई। चांदी में यह तेजी औद्योगिक मांग और निवेश दोनों के संतुलन का परिणाम मानी जा रही

है। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में चांदी की मांग लगातार बनी हुई है, जिससे इसकी कीमतों को समर्थन मिल रहा है।

दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे बड़े बाजारों में भी लगभग यही रुझान देखने को मिला, जहां सोने की कीमतें सीमित दायरे में रहीं, जबकि चांदी ने हल्की बढ़त के साथ बाजार को सहारा दिया। क्षेत्रीय बाजारों में भी कोई बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला, जो इस बात का संकेत है कि कीमतों की दिशा राष्ट्रीय स्तर पर एक समान बनी हुई है।

हालांकि सप्ताहांत की इस हल्की नरमी के विपरीत, पूरे सप्ताह के आंकड़े काफी मजबूत तस्वीर पेश करते हैं। बीते सात दिनों में 24 कैरेट सोने की कीमत में लगभग 2,860 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त दर्ज की गई है, जो निवेशकों के भरोसे और बाजार में मांग के मजबूत बने रहने को दर्शाती है। इसी तरह 22 कैरेट सोने में भी करीब 2,600 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है। यह बढ़त उस समय आई है, जब वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और आर्थिक दबाव लगातार बने हुए हैं।

चांदी की बात करें तो इसमें भी पूरे सप्ताह के दौरान उतार-चढ़ाव के बावजूद कुल मिलाकर लगभग 5,000 रुपये प्रति किलोग्राम का उछाल देखने को मिला है। यह संकेत देता है कि निवेशकों की नजर केवल सोने पर ही नहीं, बल्कि चांदी पर भी बनी हुई है, जो कम कीमत में बेहतर रिटर्न का विकल्प प्रदान करती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चल रही गतिविधियों का सीधा असर घरेलू सर्राफा बाजार पर पड़ रहा है। डॉलर की चाल, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, वैश्विक महंगाई और केंद्रीय बैंकों की नीतियां जैसे कारक सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक सुस्ती की आशंकाएं भी निवेशकों को सुरक्षित निवेश की ओर आकर्षित कर रही हैं, जिससे सोने की मांग बनी हुई है।

घरेलू स्तर पर भी शादी-विवाह के सीजन और त्योहारी मांग की उम्मीदें बाजार को समर्थन दे रही हैं। हालांकि ऊंची कीमतों के चलते खुदरा खरीदारी में थोड़ी सुस्ती देखी जा रही है, लेकिन निवेश के नजरिए से सोने की मांग मजबूत बनी हुई है। यही कारण है कि कीमतों में मामूली गिरावट के बावजूद बाजार का समग्र रुझान सकारात्मक बना हुआ है।

विश्लेषकों का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में यदि वैश्विक परिस्थितियां इसी तरह अनिश्चित बनी रहती हैं, तो सोने और चांदी की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि बीच-बीच में मुनाफावसूली के कारण छोटी गिरावटें आती रहेंगी, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से बाजार का रुख अभी भी मजबूती की ओर संकेत कर रहा है।

कुल मिलाकर, सप्ताहांत पर आई हल्की नरमी को बाजार की सामान्य चाल के रूप में देखा जा रहा है, जबकि साप्ताहिक आधार पर तेजी का ट्रेंड निवेशकों के विश्वास को मजबूत करता है। सर्राफा बाजार इस समय एक संतुलित स्थिति में नजर आ रहा है, जहां अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के बावजूद दीर्घकालिक संभावनाएं सकारात्मक बनी हुई हैं। ऐसे में निवेशकों के लिए यह समय सतर्कता के साथ-साथ अवसरों को पहचानने का भी है, क्योंकि सही रणनीति के साथ कीमती धातुओं में निवेश भविष्य में बेहतर लाभ का मार्ग खोल सकता है।